श्री अमर सिंह: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने यह बताया है कि इनकम टैक्स के अधिकारी भी बढ़ा दिए गए हैं और आपके विभाग में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। आप कृपया यह बताएं कि दिल्ली में चार सालों से कितने इनकम टेक्स के मामले लम्बित पड़े हुए हैं। आपकी पूरी एफिसिएंशी के बावजूद, आपकी पूरी प्रयत्नशीलता के बावजूद चार सालों से दिल्ली सर्किल में इनकम टैक्स के मामले लम्बित क्यों हैं? यदि आपके यहां सब कुछ ठीक चल रहा है तो अभी तक यह प्रक्रिया क्यों लटकी हुई है, क्यों चार-चार सालों से पड़े हैं?

श्री वी॰ धनंजय कुमार: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी है, कभी-कभी करदाताओं की वजह से ये मामले लम्बित रह जाते हैं। हमारा सतत प्रयास है कि समय से सभी करदाताओं की समस्याओं को हल किया जाए और जितना कर वसूल करना है, वह वसूल हो जाए।

राजस्थान में इंदिरा लिफ्ट योजना को स्वीकृति दिया जाना

*124. **श्री मूल चन्द मीणा:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार की ओर से सवाई माधोपुर और करौली जिलों में गंगापुर सिटी, हिण्डन, रोजायीय, सपोटरा, बौली नादोती, बामनवास तहसीलों के किसानों द्वारा सिंचाई किए जाने के प्रयोजन से चम्बल नदी पर इंदिरा लिफ्ट योजना के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) राजस्थान सरकार से 104845 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 675 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इंदिरा लिफ्ट योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून, 2000 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई है। इस योजना की स्वीकृति विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों के प्रेक्षणों की राज्य सरकार द्वारा अनुपालन करने पर निर्भर है।

Clearance to Indira Lift Yojana In Rajasthan

†*124. SHRI MOOLCHAND MEENA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal viz. Indira Lift Yojana on River Chambal from the state Government of Rajasthan for the purpose of irrigation by the farmers of tehsils of Gangapur city, Hindaun, Rojayiya, Sapotara, Bauli, Nadoti and Bamanvas in the districts of Sawai Madhopur and Karoli; and

(b) if so, by when it is likely to be sanctioned by Government alongwith the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN SETHI): (a) and (b) The deailed project report of Indira Lift Yojana estimated to cost Rs. 675 crore for providing irrigation to an area of 104845 hectares has been received in Central Water Commission from Government of Rajasthan during June, 2000. Clearance of the Yojana is linked with compliance of observations of various Central Appraising agencies by the State Government.

श्री मूलचन्द मीणा: चेयरमैन सर, मैंने यह देखा है कि यह परियोजना, इंदिरा लिफ्ट योजना राजस्थान के एक ऐसे एरिया के लिए बनाई गई थी जिसमें हमेशा अकाल और सूखे से पीड़ित किसान रहते हैं। महोदय, 1980 से मैं देखता आ रहा हूं कि जो भी चीफ मिनिस्टर राजस्थान में बनता है वह उस एरिया में जाता है और वह इस लिफ्ट परियोजना की घोषणा करता है। लेकिन अब जाकर, जून के महीने में इसका पूर्ण प्रस्ताव बनकर आया है। इसके ऊपर आबजक्शन लगते रहे। प्रस्ताव आते रहे और आबजक्शन लगते रहे और अब आबजक्शन पूरे होने पर यह कंपलीट हुआ है। माननीय मंत्री जी द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूर करने में राज्य सरकार की अनुपालना का एक बहाना इस उत्तर में आया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए आपके क्या-क्या मापदण्ड हैं और यह परियोजना क्या उन मापदंडों पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है?

SHRI ARJUN SETHI: Sir, let the hon. Member know that irrigation being a State subject, irrigation projects are being planned, formulated and executed and also funded by the State Governments concerned, according to their priorities. So, unless these clarifications

†Original notice of the question was received in Hindi.

are received from the State Government concerned—various agencies are involved in the proces of clearance of this particular project—I am afraid I cannot assure here as to by what time this can be clearned and by what time this can be implemented.

श्री मूलचन्द मीणा: माननीय मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस परियोजना का प्रस्ताव क्या आपके पास आ गया है और इसको आप कब तक मंजूर कर देंगे?

श्री संघ प्रिया गौतम: अभी जून में आया है:—

श्री टी॰ एन॰ चतुर्वेदी: क्लेरीफिकेशन मांगे हैं उसके बाद होगा।

श्री मूलचनद मीणा: यह जून में आई है और परियोजना पर जितने आबजक्शन थे वह कम्पलीट, पूरे हो गए हैं इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कब तक इस परियोजना को केन्द्र सरकार मंजूरी दे देगी क्योंकि राजस्थान के लिए यह जरूरी है। राजस्थान सरकार से आपको क्या-क्या अनुपालना करानी है इसके बारे में स्पष्ट करें कि ये-ये चीजें राज्य सरकार बताए और केन्द्रीय सरकार इसको कब तक पूरी मंजूरी दे देगी यह मैं जानना चाहता हूं।

SHRI ARJUN SETHI: Mr. Chairman, Sir, this particular project was received in the month of June by the Central Water Commission under my Ministry. They have not yet complied with the clarifications sought from the State Government by the CWC. I am afraid I cannot assure the hon. Member as to what time this project can be cleared. Unless the clarifcations are complied with by the State Government, the Centre cannot help. The hon. Member, on his part , can persuade his State Government so that these clarifications come to the Ministry of Water Resources soon. I will certainly help if this comes early.

*125. [The Questioners (Shri Sanjay Nirupam and Shri B.P. Panda) were absent. For answer, *vide* page 28 infra]

MR. CHAIRMAN: Question No. 126. Shri Dina Nath Mishra.

SHRI DINA NATH MISHRA: Question No. 126.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over